

## किसानों को राहत

छोटे और सीमांत खेतियों को व्यापक कृषि संकट से निकालने की कोशिश में केंद्र सरकार ने बजट में वित्तीय सहायता की घोषणा की थी. गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के खाते में नकदी डालने की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ हो गया है. इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में तीन समान किस्तों में सालाना छह हजार रुपये स्थानांतरित किये जायेंगे. पहले चरण में एक करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभार्थी होंगे और कुछ दिनों में एक करोड़ अन्य परिवारों को राहत मुहैया करा दी जायेगी. अच्छी फसल होने के बावजूद किसानों को उपज का उचित दाम मिल पाने में मुश्किल हो रही है. सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद भी मंडियों में खरीद की रफ्तार धीमी है. इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे किसानों को भुगताना पड़ रहा है. हमारे देश में दो हेक्टेयर यांनी करीब पांच एकड़ जमीन से कम का मालिकाना रखनेवाले खेतिहर 85 फीसदी से अधिक हैं. ये खेती की लागत के साथ अपने जीवनयापन के लिए इसी काशतकारी पर निर्भर हैं. ऐसे में उम्मीद यही है कि नकदी की

**इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में तीन समान किस्तों में सालाना छह हजार रुपये स्थानांतरित किये जायेंगे.**

आमद इन्हें फौरी तौर पर राहत देगी, लेकिन सभी लाभुकों तक 31 मार्च तक दो हजार रुपये की पहली किस्त पहुंचाने में कई मुश्किलें हैं. रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकार के पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम के पास 3.2 करोड़ आवेदन भेजा है. इनमें से 55 लाख लंबित हैं और 1.7 करोड़ को मंजूर कर लिया गया है. सिस्टम ने 84 लाख आवेदन निरस्त कर दिया है. नामंजूर हुए 33 फीसदी आवेदनों को फिर से भेजना पड़ सकता है. एक चुनौती लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू होनेवाले आदर्श आचार संहिता की भी है. लाभुकों के खाते में पैसे पहुंचाने की तारीख 31 मार्च से पहले ही संहिता लागू हो जायेगी. चूंकि बजट में की गयी घोषणा के मुताबिक यह योजना दिसंबर से लागू की गयी है, इसलिए तब तक पैसे के हस्तांतरण में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, लेकिन संहिता लागू होने से पहले शुरुआती किस्त के लाभुकों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी करने से इस प्रक्रिया में आसानी होगी. चुनावी मौसम हो या न हो, किसी मसले पर राजनीति होना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्थायी स्वभाव है. बहुत संभव है कि संहिता और हस्तांतरण भी एक मुद्दा बन जाये तथा विवाद का निबटारा चुनाव आयोग को करना पड़े. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि लाभुकों की पहचान करने में सभी राज्यों ने एक-समान उत्साह नहीं दिखाया है. खबरों के मुताबिक, आवेदनों में 67 फीसदी हिस्सा भाजपा या भाजपानित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राज्य सरकारों ने भेजा है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों से सिर्फ दो फीसदी आवेदन ही आये हैं. अकेले उत्तर प्रदेश से करीब 30 फीसदी आवेदन भेजे गये हैं और पश्चिम बंगाल से किसी भी लाभुक का नाम प्रस्तावित नहीं है. संभव है कि आगामी दिनों में यह असंतुलन दूर हो जाये और आचार संहिता के लागू होने से पहले सभी सही लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान हो जाए.



बोधि वृक्ष

## कृष्ण का रूप

यद्यपि भगवान कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं. उनके योगमैय या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं. तो वे भी उनसे पृथक रहते हैं. यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उरन होकर भगवान कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं, वे इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं. अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रहते हैं. भगवान कृष्ण का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण को भक्तिभाव में ग्रहण कर लेता है, वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है. यदि भगवान कृष्ण का शरणगत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहारकर्ता है, हम मनुष्यों के जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है! अज्ञानी नहीं समझ सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होनेवाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं. वृक्ष तथा सूक्ष्मता तो उनकी विचारशक्ति से परे होते हैं. अतः वे सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है. यदि हम भगवद्गीता तथा श्रीमद्भगवद जैसे प्राणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्णतत्व समझने के लिए करें, इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करें, तो समझ सकते हैं कि कृष्ण श्रीभगवान हैं. वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं. श्रीमद्भगवद में शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा- भगवान श्रीकृष्ण ने बलराम के साथ-साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किये.

स्वामी प्रभुपाद

## कुछ अलग

# हम सब चाइनीज!

लगता है पूरी दुनिया ही चाइनीज हुई जा रही है. मोबाइल अधिकांश चाइनीज हो लिये हैं या कोरियन, बचे-खुचे मोबाइल अमेरिकन या जापानी हैं और उसके भी बचे-खुचे जो हैं. वह भारतीय मोबाइल रह गये हैं. हर दस में सात स्मार्टफोन चाइनीज हैं. यूँ हम सघन घणों बहुत ही भारी राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हैं. भावनाएं राष्ट्रीय हैं, पर फोन चाइनीज हैं. सपने अमेरिकन हैं.

### आलोक पुराणिक

वरिष्ठ व्यंग्यकार  
puranika@gmail.com

पाकिस्तानी आतंक के पीछे चीन का फाइनेंस है. चीन का फाइनेंस कहां से आता है? जो वह उन भारतीयों की जेब से भी आता है, जिनके हर दस स्मार्टफोनों में से सात चाइनीज होते हैं. दस में सात स्मार्टफोन चाइनीज हैं, पर दिल हिंदुस्तानी है, जिसकी भावनाएं चाइनीज टाइप हैं, कतई फर्जी हैं. दिल हिंदुस्तानी बचा है. पर कड़ियों के दिल का ऑपरेशन हो चुका है. दिल में ऑपरेशन के बाद एक उपकरण डाल दिया जाता है, जिसे स्टेंट कहा जाता है, यह चाइनीज हो सकता है. ऐसे मामलों में दिल भी चाइनीज माना जा सकता है. कभी-कभी लगता है कि दिल भी चाइनीज ही हो लिया है, जो एक के बाद एक के बाद चाइनीज स्मार्टफोनों पर आये चले जा रहे हैं. चीन बहुत गहरे तक घुसा हुआ है, दिल से लेकर दिमाग तक, मोबाइल से लेकर स्टाल्ड तक. बड़े-बड़े भारतीय स्टार चाइनीज ब्रांडों के इस्तेफार कर रहे हैं. खैर, फिल्म स्टारों की बात तो समझ आती है, पर इधर बैडमिंटन जगत के कुछ बड़े नामों के चाइनीज ब्रांडों से जुड़ने की खबरें आयीं. खिलाड़ी

भी चाइनीज हो लिये हैं. खिलाड़ी क्या करें, खिलाड़ियों की आफत यह है कि जब तक वह तमाम चीजों को बेचते न दिखें, उन्हें बड़ा नहीं माना जाता. क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं. पर उनके बारे में एक सवाल उठा कि वह तो तमाम ब्रांड बेचते हुए नहीं दिखायी देते, तो हम उन्हें बड़ा खिलाड़ी क्यों मान लें. बड़प्पन सिर्फ खेल में ही नहीं चाहिए, बड़े रिकॉर्ड सेल्समैनशिप में भी चाहिए. भारतीय आइडम त मिल्ने बेचने को तो जापान, चीन कहीं के भी बेच लो. अब बिकवानेवाले ही चीन से आ रहे हैं, तो खिलाड़ी क्या करें. महानता का रास्ता अब चाइनीज होने के रास्ते से जाता है, दिल से भी दिमाग से भी चाइनीज. हम भी चाइनीज, तुम भी चाइनीज. वे भी चाइनीज. ये भी चाइनीज. चीन सिर्फ देश नहीं है, चाइनीज सुनते ही घंटिया और फर्जी क्वॉलिटी का ध्यान आता है. पर यही तो हम सब भी हो लिये हैं. मोबाइलों की तरह. चीन जो एक तरफ भारत से पैसा कमाता है, दूसरी तरफ भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंक मसूद अजहर को बचाता भी है. चीन का फंडीपना तो समझ में आता है, यह उसका चरित्र है. पर भारतीय भी कतई चाइनीज हुए जा रहे हैं, सिर्फ स्मार्टफोनों के मामले में ही नहीं.

एक चाइनीज फोन से दूसरे चाइनीज फोन पर मैसेज जाता है- राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, हमें देश बचना है. चाइनीज फोन पर मैसेज चाइनीज फोन को जा रहा है, पर बचाना उससे भारत देश है. कितना चाइनीज विचार है ना यह?



रविभूषण

वरिष्ठ साहित्यकार

ravibhushan1408@gmail.com

**नामवर एक महान शिक्षक और बड़े आलोचक थे. अब उनकी अनुपस्थित उपस्थिति है. शरीर से अनुपस्थित, पर अपनी कृतियों में सदैव उपस्थित. नामवर नामवर थे और हमेशा रहेंगे भी. उनकी नामवरियत पर विचार भी होता रहेगा.**

## देश दुनिया से

### सिर्फ प्रतिबंध नहीं, सख्त कार्टवाई करे पाकिस्तान

हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के साथ ही उससे जुड़ी संस्था फलहा-ए-इंसानियत पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) ने यह फैसला लिया. प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ कि राज्य को आतंकवादियों का बंधक नहीं बनने दिया जायेगा. जमात-उद-दावा निश्चित रूप से लश्कर-ए-तैयबा का ही अवतार है, जिससे पाकिस्तान को बदनाम होना पड़ा है. हालांकि, यह प्रतिबंध काफी नहीं है, कार्टवाई जरूरी है अगर ऐसे संगठनों के खिलाफ आतंक फैलाने के सबूत हैं. पिछले दो दशक से पाकिस्तान में ऐसे कई आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा, लेकिन वे फिर किसी और नाम से खड़े होते रहे. पुलवामा हमले के बाद इमरान सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरकारों को आतंक से गंदा करनेवाले लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं. ये सारे कदम यह साबित करते हैं कि ये संगठन न सिर्फ पाकिस्तान की अंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, बल्कि इससे पड़ोसी देशों से रिश्ते भी खराब होने की संभावना है. पाकिस्तान को इन संगठनों पर सख्त कार्टवाई करने की जरूरत है.



आशुतोष चतुर्वेदी

प्रधान संपादक, प्रभात खबर

ashutosh.chaturvedi  
@prabhatkhabar.in

**कश्मीर में जैसे हमारे जवान शहीद होते हैं, वैसे ही वहां के लाल भी इन आतंकवादियों की गोलियों के शिकार होते हैं. आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है, तो गलती नहीं करनी है. उत्तेजना में हम आप आपा न खोंएं.**

सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान हमेशा इस हमले में अपनी भूमिका को खारिज करता आया है. हमें एक और पड़ोसी देश चीन पर भी निगाह रखनी होगी, जिसकी मदद से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी. यह कितना हास्यास्पद है कि बावजूद इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सबूत मांग रहे हैं. यह जगजगह है कि जैश मोहम्मद ने पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में अपना मुख्यालय बना रखा है और इसका मुख्या मसूद अजहर यहीं से अपनी आतंकी गतिविधियां संचालित करता है. इसके पहले तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ ने अपने देश की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में अब भी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं. नवाज शरीफ ने कहा था कि आप उन्हें गैर सरकारी किरदार कह सकते हैं, लेकिन हम उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते? नवाज शरीफ का बयान सार्वजनिक होने के बाद पाक सेना उनके खिलाफ हो गयी थी और उसने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया. हम आप जानते हैं कि 26 नवंबर, 2008 के खतरनाक आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गये थे. उनमें से एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ लिया गया था. भारत द्वारा पुख्ता सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान हमेशा इस हमले में अपनी भूमिका को खारिज करता आया है. हमें एक और पड़ोसी देश चीन पर भी निगाह रखनी होगी, जिसकी मदद से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

दबावों से बचता आ रहा है. देश की जनता को भी इस बात को लेकर जागरूक करना होगा कि चीन आपका शुभचिंतक नहीं है. चीन के अड़गे के कारण आत्मघाती हमले के एक हफ्ते बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसकी कड़ी निंदा कर पाया. चीन ने पाकिस्तान को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था. चीन ने इस बात की पूरी कोशिश की थी कि यह बयान जारी न हो पाए. भारतीय प्रयासों और अमेरिका के समर्थन के कारण ही सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को इसकी मंजूरी मिल सकी. पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा परिषद में एक हफ्ते भारी खींचतान चलती. पुलवामा पर 15 फरवरी को निंदा का बयान जारी होने वाला था, लेकिन चीन इसमें बदलाव करने के लिए लगातार इसे आगे बढ़वाता रहा. सुरक्षा परिषद के सदस्य देश 15 फरवरी को अपना बयान जारी करनेवाले थे, लेकिन चीन ने इसे आगे बढ़वाते हुए 18 फरवरी तक का समय मांगा. प्रक्रिया को टालने के लिए चीन ने दो बार इसमें बदलाव के प्रस्ताव रखे. चीन चाहता था कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद को दोषी ठहराये जाने का जिज्ज न किया जाए. बावजूद इसके सुरक्षा परिषद ने पुलवामा के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और अपने बयान में जैश का जिज्ज करने का भी भारत की कोशिशों में बार बार अड़ंगा लगाता आया है.

भारत और पाकिस्तान को अलग हुए 70 साल से अधिक का अरसा हो गया, लेकिन रिश्ते आज तक सामान्य नहीं हो पाये हैं. विभाजन के रूप में हमने आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है. विभाजन के दौरान हुई हिंसा में लगभग पांच लाख लोग मारे गये थे और करीब डेढ़ करोड़ लोगों को अपना घर-बार छोड़ कर शरणार्थी बनना पड़ा था. दुनिया में आजादी की इतनी बड़ी कीमत कहीं अदा नहीं करनी पड़ी है. इतिहास के इस काले अध्याय को हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए.



## आपके पत्र

### अब गेंद सरकार के पाले में

पुलवामा आतंकी हमले का आक्रोश अब क्रिकेट के मैदान पर भी दिख रहा है. वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सीओए ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है. अब पाकिस्तान के साथ भिड़ंत होगी या नहीं, इसका फैसला केंद्र सरकार को करना है, जिसे बीबीसीआइ भी स्वीकार करेगी. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी कहा कि इस संबंध में जो भी फैसला लिया जायेगा, वह उन्हें मंजूर होगा. सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने कहा था कि विरोधी की बजाय हमें पाकिस्तान से खेला चाहिए और उसको हरा कर मुहंतोड़ खेला देना चाहिए. ऐसा नहीं करने से भारतीय टीम को काफी नुकसान भी हो सकता है. चेतन चौहान ने भी कहा है कि वर्ल्ड कप जैसे वैश्विक टूर्नामेंट में पाकिस्तान का बहिष्कार करना आसान नहीं है. अगर टीम इंडिया मैच नहीं खेलती है, तो उस पर बैन और जुर्माना लगा सकता है. अब सरकार के निर्णय पर सबकी नजर है और इस पर निर्णय करना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा.

अमन सिंह, प्रेमनगर,बरेली

### जहरीली शराब से मौत

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब असम में भी जहरीली शराब के सेवन से मौत की खबर आ रही है. अब तक लगभग 124 लोगों की मौत हो चुकी है. यूपी और उत्तराखंड में सैकड़ों लोग जहरीली शराब की चपेट में आ कर अपनी जांच गंवा चुके हैं. यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जहरीली शराब का घंघा क्यों नहीं रुक रहा? वास्तविकता है कि यह अवैध कारोबार दिन-प्रतिदिन अपना पैर फैलाता ही जा रहा है. न जाने देश में कितनी जगहों पर इस तरह के अवैध धंधे चल रहे हैं. कोई कार्टवाई न होने के कारण इनके कारोबारियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है. पुलिस-प्रशासन हाथ-पर-हाथ धरे बैठे हैं. इनकी आंखें तब खुलती हैं, जब घटना हो जाती है. सरकार को इन कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्टवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी जगह इस तरह लोगों की मौत न हो.

शुभम गुप्ता, धनबाद

### रात में ट्रैफिक सिग्नल

रांची में नये ट्रैफिक सिग्नल और वीडियो कैमरे लगा कर ट्रैफिक की समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है. वैसे तो यह बहुत ही अच्छा प्रयास है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आयी कि रात के 11 बजे, जब सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं होता, उस समय भी ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ और कुछेक गाड़ियों को रात में रोकना और उनका समय बर्बाद करना जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता को उजागर करता है. देश के अन्य शहरों के मॉडल का इस्तेमाल करें, तो ऐसी समस्या नहीं आयेगी. बड़े शहरों में रात में (नौ-दस बजे के बाद) सभी ट्रैफिक सिग्नल को पीला कर दिया जाता है, ताकि लोगों को अनावश्यक रुकना न पड़े और अपनी सूझबूझ से आसानी से पार कर लें. उम्मीद है जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देगा.

मृणाल कान्ति रक्षित, सेक्टर-2, धुर्वा, रांची

**पोस्ट करें:** प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैसल करें:** 0651-2544006, **मेल करें:** eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है